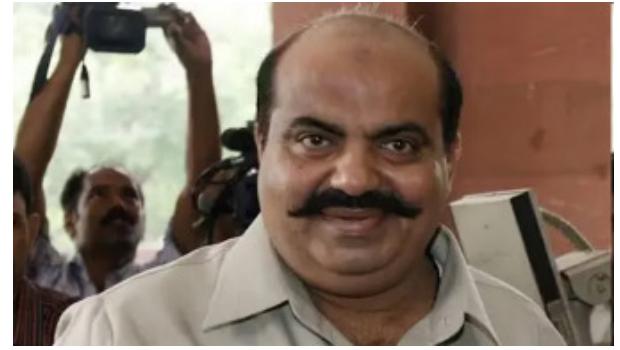




**माफिया को ईडी ने नोटिस जारी कर कहा- बंगले का अवैध निर्माण ध्वस्त कराकर करें सुचित**

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)  
प्रयागराज। प्रयागराज विका  
प्राधिकरण की नजर में माफि

नोटिस जारी किया है। दरअसल, हाईकोर्ट चौराहे पर आंबेडकर प्रतिमा के पास उत्तर की पटरी पर



अतीक अहमद अभी तक जीवित है। प्राधिकरण ने अतीक अहमद ने नाम से बकायदा नोटिस जारी कर अवैध निर्माण ध्वस्त करने की चेतावनी दी है। यह भी चेतावनी दी है कि यदि आदेश पर अमल नहीं हुआ तो पीड़ीए निर्माण को ध्वस्त करा देगा और इसमें आने वाले व्यय को अतीक अहमद से वसूलेगा। विभाग के इस नोटिस को लेकर तरह-तरह की चर्चा चल रही है। पीड़ीए की भी अजब-गजब कार्यशैली हैरान कर देने वाली है। इस बार एक वर्ष पहले पुलिस कस्टडी में गोलियों से छलनी किए जा चुके माफिया अतीक अहमद को अवैध निर्माण रोकने के लिए पीड़ीए ने अतीक अहमद के स्वामित्व वाले नजूल भूखंड संच्या 571/2 सिविल स्टेशन नबर -दो को चार वर्ष पहले पीड़ीए ने ध्वस्त करा दिया था तीक के मारे जाने के बाद उस भूखंड पर एक बार फिर निर्माण शुरू करा दिया गया। बाहर से टिन घेरा लगाकर अंदर काम कराए जाने की शिकायत मिलने के बाद के महीनों बाद पीड़ीए की तंद्रा दूरी। पीड़ीए ने मृत अतीक अहमद के नाम से नोटिस जारी कर उसे अवैध निर्माण रोकने और खुद से ध्वस्त करने के लिए आगाह किया है। जोनल अधिकारी की ओर से अतीक के नाम भेजे गए नोटिस में लिखा है, चार वर्ष पहले छह अगस्त 2020

डांसर सपना चौधरी को एक माह के भीतर जारी करें

पासपोर्ट, कोर्ट ने एसीजेएम न्यायालय का आदेश किया रहा।

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने

प्रयागराज। डासर सपना चौधरी ने एसीजेएम अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अदालत के पास पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र

डासर सपना चौधरी के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पर रोक लगाने के द्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को सपना चौधरी द्वारा उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण या पुनः जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर निन्यच लेने और एक महीने

## बेसिक शिक्षा की वेबसाइट बता रही बिहार में कैसे पाले गाय

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)  
**प्रयागराज**। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट में सेंधमारी का मामला प्रकाश में आया है। सरकारी वेबसाइट खोलने पर ऐसी जानकारी मिल रही है जिसका विभाग से कोई लेना देना नहीं है। हैरत की बात यह है कि इसकी जानकारी भी विभागीय अधिकारियों को नहीं है। बेसिक है, जिसमें विभिन्न राज्यों की सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरें प्रसारित हो रही हैं। वेबसाइट ने अपने घोषणा पत्र में साफ-साफ लिखा है कि उसका सरकारी विभागों से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद भी सरकारी वेबसाइट से इसका लिंक हो जाना और वरन्ती खबरों का बेधिक प्रसारण होना चाहिए हैरतअंगेज है। बेसिक शिक्षा विभाग की साइट पर विभाग की



शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट आजकल यह बता रही है कि बिहार में गाय पालने की योजना का लाभ कैसे उठाएं। मध्य प्रदेश की लाडली योजना क्या है और मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड का परिणाम कैसा रहा? समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय की वेबसाइट को क्लिक करने पर भी ऐसी ही खबर सामने आ रही हैं। हैरतअंगेज है कि सरकारी पोर्टल में हुई इस सेंधमारी से अफसर पूरी तरह बेखबर हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर बेसिक शिक्षा निदेशालय, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय, एससीईआरटी, बेसिक शिक्षा बोर्ड, मिड-डे मील और साक्षरता निदेशालय का लिंक दिया गया है। इसमें बेसिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय पर क्लिक करते ही नया पेज खुलता है। इसमें विभागीय जानकारी के बजाय यूपीईएफए डॉट कॉम खुलती है। यह एक निजी वेबसाइट एक भी योजना का जिक्र नहीं होना भी चौकाता है। प्रेरणा पोर्टल का भी यही आलम है। यहां बेसिक शिक्षा का जो लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करने पर कुछ और ही खुल रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत प्रदेशभर में 1.33 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। यहां तैनात 6.26 लाख शिक्षक करीब दो करोड़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन शिक्षकों के अधिकांश कार्य इसी वेबसाइट से होते हैं। उन्हें विभागीय विवरण नहीं मिलना परेशानी का सबब है। बेसिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रताप सिंह बघेल भी वेबसाइट की हैंकिंग से हैररत में है। उन्होंने कहा कि आपके जरिये यह बात संज्ञान में आई है। पहले विभाग की कई वेबसाइट थीं, जिन्हें एक मुटेफोर्म पर लाया गया है। सभी का यहीं लिंक दिया गया है। इसमें कैसे कोई और घस गया, इसे चेक कराएंगे। ठीक भी कराएंगे।

# सुस्त कार्य संस्कृति से जिला अदालतें खो रहीं आमजन का भरोसा

(आधुनिक समाचार नेटवर्क)

प्रयागराज। कानपुर नगर के मामले में सुनवाई करते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिन्हें न्यायालयों की कार्यशैली पर सुनाया

कोर्ट का है। सक्षम न्यायालय की उपेक्षा करने वाले पक्षकार की भावना कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह राहत का हकदार नहीं हो सकता। यह अदालत की अवस्थाना में दखिल खारिज भी करा लिया। याची का कहना था कि 21 मई 2022 को जब वह अपनी जमीन का कब्जा लेने पहुंची तो भूमि विक्रेता ने कब्जा न देकर गाली गलौज और

याची का कहना था कि 21 मई 2022 को जब वह अपनी जमीन का कब्जा लेने पहुंची तो भूमि विक्रेता ने कहा न देकर गाली गलौज और



टिप्पणी की है। कहा कि ट्रायल कोर्ट की सुस्त कार्यशैली के चलते आम लोगों का जिला अदालतों के प्रति विश्वास कमज़ोर हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालतों की सुस्त कार्य संस्कृति पर तत्खंड टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने कहा, सुस्त कार्य संस्कृति से जिला अदालतों के प्रति आम लोगों का भरोसा कमज़ोर हो रहा है। कोर्ट ने कहा, लोग न्याय की तलाश में थाना-पुलिस और थकने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे, लेकिन सक्षम न्यायालय की शरण में जाने से कठरा रहे हैं। यह स्थिति खतरनाक है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कानपुर नगर की मायादेवी की जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग वाली याचिका पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दी। स्पष्ट किया, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट का काम जमीन का कब्जा दिलाना नहीं है, ऐसे विवादों के निपटारे का काम सिविल भी है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि जिला अदालतों की सुस्त कार्य संस्कृति ने लोगों के मन ने अदालतों के प्रति निराशा पैदा कर दी है। लोग चाहते हुए भी सक्षम अदालतों की शरण लेने से बच रहे हैं। यह हालात चिंताजनक होने के साथ विचारणीय भी है। कोर्ट ने कहा, अक्सर देखा गया है कि एक पक्ष को राहत देने या राहत से इन्कार करने पर न्यायिक अधिकारियों को प्रशासनिक स्तर पर होने वाली शिकायतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें यह डर भी सताता है कि कहीं उनका आदेश उच्च अदालत से पलट न दिया जाए। नतीजतन, न्यायाधीश के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना मुश्किल हो गया है। कानपुर नगर के मामले में मायादेवी के परित पीएसी लखनऊ में आरक्षी है। 15 फरवरी 2021 को घाटमपुर तहसील के गच्छपुर गांव में उन्होंने वीर बहादुर सिंह से 0.7460 हेक्टेयर जमीन का पंजीकृत बैनामा करवाया। बाद फिर मारपीट भी की। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराते हुए न्याय पाने के लिए एसडीएम, डीएम और कमिशनर के कार्यालय के चक्कर काटे। पति के कमांडेंट को भी पत्र लिखा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। विवाह होकर उन्होंने खरीदी गई जमीन पर पर कब्जा दिलाने और दोषियों के खिलाफ कारवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अदालतों की सुस्त कार्य प्रणाली के लिए वकीलों को भी जिम्मेदार ठहराया। कहा, जिला अदालत में आए दिन होने वाली हड्डाल और सीट पर बैठ कर तारीख पर तारीख लेने की संस्कृति भी मुकदमों के त्वरित निस्तारण में बाधक है। इससे लोग विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए सक्षम जिला अदालतों का विकल्प खोजते-खोजते, अधिकारियों और पुलिस थानों के चक्कर काटते हैं। फिर थककर हाईकोर्ट का रुख कर लेते हैं।

# ଆଧୁନିକ ପେଟ ହାତସ

- वाटर प्रूफ शेड
  - पार्किंग की सुविधा
  - मन्दिर की सुविधा
  - सी.सी.टीवी.
  - छोटे-बड़े कार्यक्रमों के अलग-अलग रेट
  - 45000 sq. feet. एरिया
  - हरे-भरे वातावरण
  - AC कमरा (VIP)

**CALL:** 9519313894.9415608783. 9415608710

आधुनिक समाचार पब्लिशिंग हाउस, यूपीएसआईडीसी, रेमण्ड रोड, औद्योगिक थाने के पीछे भारत पेट्रोलियम के पहले, औद्योगिक क्षेत्र, नैनी, प्रयागराज









# सम्पादकीय

कमाई से ज्यादा जरूरी है खर्च का हिसाब-किताब, खत्म हो रही बजट बनाने की अवधारणा

एक समय था जब लोग मासिक खर्चों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करने के लिए बजट बनाते थे। अब यह अवधारणा खत्म हो रही है। ईंधन की कीमतें कुछ हफ्तों में बदल रही हैं। घर पर बिजली की खपत इस बात पर निर्भर कर रही है कि आपने कितने दिन घर पर बिटाए या काम पर गए। अब बजट बनाकर वित्तीय जीवन जीना कठिन है। आजकल के युवा अक्सर सोचते हैं कि हम जितना वेतन घर ले जाते हैं, उससे कहीं अधिक कमाते हैं। हकीकत में यह ठीक उल्टा है। आप जितना कमाते हैं, उससे कम घर ले आते हुए बजट बनाते थे। अब यह अवधारणा खत्म हो रही है। ईंधन की कीमतें कुछ हफ्तों में बदल रही हैं। घर पर बिजली की खपत इस बात पर निर्भर कर रही है कि आपने कितने दिन घर पर बिटाए या काम पर गए। अब बजट बनाकर वित्तीय जीवन जीना कठिन है। फिर भी बचत और खर्चों की जांच जरूरी है। यदि कोई मासिक सैलरी पाने वाला अपने माता-पिता के साथ रहता है तो उसे कुल आय का 25-35 फीसदी निवेश के लिए बचाना चाहिए। यदि वे अकेले रह रहे हैं तो लाभगत 15-25% बचाएं। भोजन, किराया,



जब आप अपन बक खात, खच और अन्य का हिसाब-किताब करेंगे। कुछ हफ्ते पहले मुझे एक स्टार्टअप में 15 युवाओं से बातचीत का मौका मिला। 20 साल की उम्र में उनमें कुछ ऐसा आत्मविश्वास था, जो उनकी उम्र में मुझमें नहीं था। यह उनकी मानव संसाधन टीम की ओर से आयोजित एक सत्र था, जिसमें महसूस किया गया कि कर्मचारियों को बचत और निवेश के तरीकों के बारे में समझना चाहिए। लड़कियों में से एक ने खुलकर बात की और बताया कि महीने के अंत तक उसके पास निवेश के जितने पैसे नहीं बचेंगे। उसके माता-पिता उसे अक्सर याद दिलाते रहते थे कि उसने ठीक से बचत नहीं की है। वह प्रति माह लगभग एक लाख रुपये कमाती थी। बाकी लोगों का भी यही हाल था। जब उनके खर्चों के बारे में मैंने पता किया तो उन्होंने वास्तव में कभी अपने खर्चों पर नजर नहीं रखी है। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके फोन में उबर, स्विगी, अमेजन आदि जैसे एप हैं? उन सभी ने हां में सर हिलाया और फिर दर्जनों एप दिखाए जिनसे वे खाने, कपड़े, कैब और न जाने क्या-क्या ऑर्डर करते थे। फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या उसने कभी अपने बैंकिंग एप के माध्यम से अपना बैंक विवरण चेक किया है। उसका जवाब था...नहीं! एक समय था जब लोग मासिक खर्ची और वित्तीय प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करने के अन्य चाजा पर खर्च आपका आय के 45-50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। 20-25% की बचत करनी चाहिए। कमाई का 35-40 फीसदी हिस्सा कर देनारी चुकाने और गैजेट जैसी वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं। वेतनभोगी अक्सर यही सोचते हैं कि वे बताई गई आय के जितना ही कमाते हैं। यह सच नहीं है, क्योंकि अगर कॉस्ट-टू-कंपनी (सीटीसी) 12 लाख रुपये सालाना यानी प्रति माह एक लाख? रुपये हैं तो वास्तव में आपकी सैलरी मासिक 70,000 और 80,000 रुपये के बीच होती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कंपनी इसमें से टैक्स काटने के साथ? पीएफ में निवेश करती है। आर हम वेतन की गणना करें तो आपके अनुमानित वेतन का कुल ढाई से 3 महीने का वेतन आपके पास नहीं आता है। सैलरी पाने वाले लोग अम्मन सालाना सैलरी का 3 महीने की सैलरी टैक्स और दूसरे योगदान में देते हैं। इसके बिपरीत, एक बिजनेसमैन खर्ची के बाद कुल आय पर टैक्स चुकाता है, जबकि एक वेतनभोगी को पहले ही टैक्स काट कर पैसा मिलता है। फिर वे हर चीज पर जीएसठी भी देते हैं। जब मैं उनको यह समझाने में कामयाब रहा कि उनके हाथ में जितनी वास्तविक सैलरी आ रही है, वे उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उनमें से कुछ ने तो एचआर पर भड़ास निकाली शुरू कर दी। हालांकि, ये सभी डिटेल्स उनकी सैलरी स्लिप में होती है।

# लगातार बढ़ा रहा रक्कड़ सोना, जनवरी से अब तक 14.75 फीसदी की आई तेजी

ने ताजा का पड़ पढ़ा हा हुआ नया नर के केंद्रीय बैंकों ने जनवरी-फरवरी में 64 टन सोने की खरीदारी की। चीन ने फरवरी में अपना स्वर्ण भंडार 12 टन बढ़ाया है। आरबीआई ने जनवरी में 8.7 टन सोने की खरीदारी की, जो दो साल में सर्वाधिक है। सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस साल जनवरी से अब तक इसकी कीमतों

द तपरा हा हाजार, जाखेन ना बना हुआ है। 2023-24 में सोने ने 18 फौसदी रिटर्न दिया था। छु सकता है 80,000 का स्तर केडिया का कहना है कि युद्ध के दौरान सोने में हमेशा तेजी आती है। रूस-यूक्रेन और इसाइल-हमास के बाद अब ईरान-इसाइल के बीच तनाव का माहौल है। अगर इस युद्ध में मिडिल ईस्ट के देश पूरी तरह शामिल



म 14.75 फासदो का तजा दर्ज का गई है। एक जनवरी, 2024 को सोना 63,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि 12 अप्रैल को यह 73,350 रुपये वें सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। निवेश के लिहाज से सुरक्षित सोना पिछले चार कारोबारी सत्रों में 1,700 रुपये महंगा हो चुका है। केंद्रिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केंद्रिया ने बताया, वैश्विक हालात को देखते हुए सोने में तेजी

अस्मिता का सवाल उठाने से नहीं चूकते दक्षिण  
के क्षेत्रीय दल, विरोध को हवा दे रही कांग्रेस

जिस कांग्रेस ने कभी हिंदौ को प्रमुख भाषा बनाने का अभियान चलाया था, अब वही भाषायी लोकतंत्र के नाम पर इसके विरोध को हवा दे रही है। चुनावी अभियान के बीच आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। जब प्रचार तमिलनाडु जैसे राज्य में हो, तो भाषा अपने आप मुद्दा बन जाती है। चुनावी अभियान ही नहीं

सरकार और भाजपा जैसी पाटियल ही निशाने पर रहती हैं। लेकिन भाषायी अस्मिता को चुनावी मुद्दे बनाने में उस कंग्रेस का नाम भी ज़ड़ गया है, जिसने स्वाधीनत आदोलन के दौरान हिंदी को देश की प्रमुख भाषा बनाने का अभियान चलाया था। कोयबंधुर की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने तमिल लोगों

है। भाजपा ने राहुल गांधी के इसके बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की है। वैसे राहुल गांधी कांग्रेस के पहले नेता नहीं है, जिन्होंने भाषण को लेकर ऐसा बयान दिया है। केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़ रहे शशि थरूर भी चुनाव प्रचार में भाजपा पर ऐसे आरोप लगा चुके हैं। हालांकि उनके बयान

आखिरी दिनों में आंदोलन तक हो चुका है, लेकिन केरल में ऐसा नहीं है। चाहे राहुल हों या शशि थरूर, दोनों के बयानों का एकमात्र मकसद यही है कि वे अपने गोटरों को इस आधार पर अपने समर्थन में खड़ा करें और उनका मत हासिल करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे विभाजनकारी बयानों की चुनाव में

26 जनवरी, 1965 को मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई। तमिलनाडु में हुए हिंदी विरोधी आंदोलन की वजह से हिंदी देश की आधिकारिक रूप से संपर्क भाषा भी नहीं बन पाई। लेकिन तब से लेकर अब तक कावेरी और कृष्णा नदियों में काफी पानी बह चुका है। राजनीतिक बुनियाद पर भले ही दक्षिणी राज्यों में सीमित हिंदी विरोधी मानसिकता बची हुई हो, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि अब दक्षिणी राज्यों की सोच भी बदल रही है। अगर ऐसा नहीं होता, तो दूरी-फूटी ही सही, दक्षिणी राज्यों में भी हिंदी लिखने-बोलने की कोशिश नहीं होती। हिंदी सिनेमा के गाने दक्षिणी राज्यों में पसंद नहीं किए जाते। हिंदी की राह में सबसे बड़ी बाधा राजनीति रही है। अपने फायदे-नुकसान को ध्यान में रखते हुए वही स्थानीय लोकभावनाओं का कभी पक्ष, तो कभी विपक्ष में भड़काती है। महात्मा गांधी का सपना था कि आजाद भारत की अपनी भाषा हो, वह केंद्रीय भाषा बने। गुजरातीभाषी होते हुए भी उन्हें हिंदी में ही यह ताकत और संभावना नजर आई। लेकिन स्वाधीन भारत के राजनीतिक हस्तक्षेप वें चलते हिंदी आधिकारिक रूप से केंद्रीय भाषा नहीं बन पाई। राजनीति ने हिंदी विरोध के लिए अब नया बहाना ढूँढ़ लिया है। बुझापिकता और भाषायी लोकतंत्र को बनाए रखने के नाम पर उसका विरोध किया जाता है। दिलचस्प है कि केंद्रीय भाषा के तौर पर विदेशी भाषा तो स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन अपनी हिंदी नहीं। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रमुक हिंदी की घोषित विरोधी है। जब भी उसे मौका मिलता है, हिंदी विरोध में अपनी आवाज मुखर करने से वह नहीं हिचकती। जब नई शिक्षा नीति लागू हो रही थी, तब भी उसने आरोप लगाया था कि हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है। द्रमुक इंडिया गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। लेकिन गौर किया जाना चाहिए कि तमिलनाडु में जब प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ प्रचार में उत्तरते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं। उनके भाषणों का तमिल में अनुवाद होता है। अगर तमिल जनता हिंदी विरोधी होती, तो वह दैर्घ्य से इन नेताओं का भाषण नहीं सुनती। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि तमिल लोगों ने इन नेताओं के हिंदी भाषणों में अरुचि दिखाई हो। साफ है कि हिंदी को लेकर दक्षिण का लोकमानस बदल रहा है, अगर नहीं बदल रही है, तो वह है राजनीति। हालांकि कंप्रेस तर्क दे सकती है कि एक भाषा थोपने की उसके नेताओं की बात के पीछे हिंदी विरोध नहीं है। लेकिन केंद्रीय भाषा के रूप में एक भाषा का मतलब स्वतंत्र भारत में हिंदी ही है। ऐसे बयानों से राजनीतिक फायदा जो भी हो, भाषायी मानस का नुकसान होता है।



इरान-इस्लाइल ट्रिपराष स पर भूमिका पर असर लाजिमी, तेल की कीमतों में लगेगी आग

हुकूमत ने कोई प्रतिक्रिया जताई  
जबकि पड़ोस में युद्ध से पाकिस्तान  
ही नहीं, अन्य मुल्कों पर भी असर

कोई बयान नहीं आया, विदेश मंत्री  
का भी नहीं। मैंने ट्वीट करके  
प्रधानमंत्री को आपातकालीन सुरक्षा

लेकिन आम तौर पर स्थानीय प्रशासन इससे निपटता है। सीमा पर विशेष रूप से पेट्रोल की तस्करी

की और दावा किया कि ईरान के भीतर पाकिस्तान-विरोधी आतंकी गुटों को सुरक्षित पनाह मिली हुई।

में अपने राजनयिक मिशन पर हमले और वरिष्ठ अधिकारियों की मौत का बदला लेगा, लेकिन शुरू हुआ है, इसाइल ने 30 हजार से ज्यादा फलस्तीनियों की गाजा में हत्या कर दी है। उन्होंने पूछा



की कीमतें तो आसमान छूने लागेंगी। पिछले रविवार को जैसे ही पाकिस्तान के लोग जगे, उन्हें यही खबर मिली कि ईरान ने इसाइल पर हवाई हमला कर दिया है और सैन्य अभियान अब भी जारी है। मेरी तत्काल प्रतिक्रिया थी कि इसाइल भी पलटवार करेगा और इस क्षेत्र में एक नया युद्ध शुरू होने जा रहा है। ईरान और इसाइल के बीच स्थित कई अरब देश भी इससे प्रभावित होंगे। हालांकि पिछले रविवार पाकिस्तान की सड़कों पर जीवन सामान्य था और आम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, कि ईरान ने युद्ध की घोषणा कर दी है। जो लोग टीवी देख रहे थे केवल वही इस खबर में दिलचस्पी ले रहे थे, अन्यथा किसी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहां तक कि पाकिस्तान की हुक्मूत भी चुप थी। हालांकि पाकिस्तान में एक्स-

स्थिति बहुत अप्रत्याशित थी औं औं  
यह युद्ध किसी भी दिशा में जा-  
सकता था। हालांकि दुनिया की को-  
सरकारें एक-दूसरे तथा ईरान औं औं  
इसाइल के संपर्क में थीं, लेकिन  
पाकिस्तान के मंत्री एवं अधिकारीं  
बिल्कुल शांत थे। अन्य मुल्कों के-  
तरह पाकिस्तान में तेल बहुत महंगा  
है और आर्थिक रूप से कमजोर  
लोगों की पहचं से बाहर है। इसलिए  
मेरा पहला विचार यही था कि अगर  
पड़ोस में युद्ध होता है, तो तेल के-  
कीमतें आसमान छूने लगेंगी। पड़ोस  
में युद्ध पाकिस्तान के लिए को-  
नई बात नहीं है। हममें से कई लोग  
भारत के साथ युद्ध से गुजर चुके  
हैं और अफगानिस्तान भी कभी शांत  
नहीं रहा है। इसलिए अब दूसरी  
पड़ोसी ईरान को युद्ध में शामिल  
होते और इसके प्रभाव को पसरात  
देखना डरावना था। लंबी और साईं  
सीमा के साथ ईरान पाकिस्तान का

नीचे तक के अधिकारियों की इसमें  
मिलीभगत होती है और यह लगातार  
उनकी नाक के नीचे होता है।  
व्यवसायी अक्सर शिकायत करते  
हैं कि ईरान से होने वाली तस्करी  
उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा  
रही है, लेकिन सरकार उस पर  
कोई ध्यान नहीं देती। एक बार  
सरकार ने घोषणा की कि वह मात्र  
तस्करी को बर्दाश्त नहीं करेगी और  
उससे कठोरता से निपटेगी। इससे  
थोड़े समय के लिए तस्करी पर  
विराम लगा, लेकिन क्वेटा के  
दुकानदारों ने ईरानी दरी की कीमत  
बढ़ा दी। उनकी शिकायत थी कि  
इन दरियों की भारी मांग है, लेकिन  
सीमा पार से दरियां नहीं आती हैं,  
इसलिए कीमत बढ़ गई है। लेकिन  
तस्करी सौ फीसदी कभी नहीं रकी  
और अब भी जारी है। कुछ समय  
पहले ईरान ने बलूचिस्तान के भीतर  
हवाई हमले करके दुनिया को चौका-

पाकिस्तान और ईरान, दोनों जानते हैं कि उनकी जमीन पर आतंकवादी गुट है, तो उन्हें दोनों मुल्कों द्वारा सरक्षण कर्यों दिया जाता है। क्या दोनों मुल्क उन्हें प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? इससे दोनों मुल्कों के नागरिकों को बेहद खतरनाक और भ्रामक संदेश जाता है, जो एक-दूसरे को अपना मजबूत सहयोगी और मुस्लिम भाईचारे के हिस्से के रूप में देखते हैं और कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं। खेर, दोनों पक्षों के पीछे हटने से समझदारी कायम हुई। ईरान ने कूटनीतिक रिश्ते की बहाली के लिए अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेजा। अब दोनों मुल्कों के रिश्ते में ईरानी राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। इसाइल पर ईरान के हमले ने, जिसमें अमेरिका, अन्य पश्चिमी देश एवं

करने वाला इसाइल हमले से हेरान रह गया। अमेरिका के नेतृत्व में बाहरी शक्तियां उसकी मदद के लिए आगे आई। पश्चिमी समर्थकों की मदद के बिना इसाइल अपनी रक्षा करने में असमर्थ था और वहां जान-माल का भारी नुकसान होता। दिलचस्प है कि जब इसाइल ने कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन कर सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया, तो पश्चिमी देशों ने उसकी आलोचना नहीं की, लेकिन जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, तो वे सभी ईरान की आलोचना करने लगे। दूसरी बात को इस हफते पाकिस्तान दौरे पर आए सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि कुछ

## संक्षिप्त समाचार

आरबीआई के निशाने पर आए ये पांच बैंक, कई नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना (आधुनिक समाचार नेटर्क) मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग-अलग रेस्युलेटरी नॉर्म के उल्लंघन के लिए पांच सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने जिन सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है उनमें राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, द कंगड़ा को-



ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ), जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल और जिला सहकारी बैंक, देहरादून शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक द कंगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली) राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ) जिला सहकारी बैंक गढ़वाल और जिला सहकारी बैंक देहरादून पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन पांच बैंक पर कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने बांधने के लिए रख रखते हैं उन्हें लाभ पहुंचाया है। बैंक पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर 43.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है सेंट्रल बैंक ने द कंगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ) और जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल प्रत्येक बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनी जिला को-ऑपरेटिव बैंक देहरादून पर 2 लाख रुपये की पेनटी लाई है सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाने की जानकारी देते हुए बताया कि इन बैंक पर पेनटी अलग-अलग रेस्युलेटरी नियमों का पालन न करने के लिए लगाई कई हैं। इसके साथ ही इन पेनटी का उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए एग्रीमेंट या किसी भी लेनदेन की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

इन्फोसिस को चौथी तिमाही में 30% का जबरदस्त मुनाफा, जानिए कैसा रहा शेयर का हाल (आधुनिक समाचार नेटर्क) नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस ने युक्ता को बताया कि मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही में उसका समेत लाभ 30 प्रतिशत बढ़कर 7,969 करोड़ रुपये हो गया। शेयर बाजार को



दी गई सूचना में कंपनी ने कहा कि एक साल पहले की समाप्त अवधि में उसने 30 प्रतिशत बढ़कर 7,969 करोड़ रुपये हो गया है। इसके साथ ही उसका कुल राजस्व 1.3 प्रतिशत बढ़कर 37,923 करोड़ रुपये हो गया। आज कंपनी के शेयर बढ़कर के साथ बढ़ रहे हैं। इन्फोसिस का समेत राजस्व 1.3 बढ़कर 37,923 करोड़ रुपये हो गया। यह एक साल पहले हो गया है। कंपनी को अगले वित्त वर्ष में एक से तीन प्रतिशत की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है। परे वित्त वर्ष में हुए शुद्ध लाभ की बात करें तो यह 26,233 करोड़ रुपये रहा।

## 'जल, थल और वायु क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा अंतरिक्ष'

(आधुनिक समाचार नेटर्क)  
नई दिल्ली। यीक ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल चौहान ने कहा है कि युद्ध के लिहाज से भविष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र वायु समझी और थार क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा।



भविष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र वायु, समुद्री और थल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत दुनिया में प्रमुख सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में उभरेगा। कुछ साल पहले तक जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी अब वो हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत दुनिया में प्रमुख सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में उभरेगा।

हमारे पास समाचार और अंतरिक्ष क्षेत्र वायु, समुद्री और थल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत दुनिया का विस्तार अनंत है। अन्य सभी सीमाओं की तरह इसकी सीमा को स्पष्ट रूप से परिभ्राष्ट करना मुश्किल है। अंतरिक्ष के हस्तय को समझके लिए मानव जाति को अभी लंबा रास्ता तय करना है। भारत उस यात्रा का हिस्सा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र के गणनायान कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ले रहे चार अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी बात की। जनरल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष को युद्ध के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मेरा मानना है कि यह पहले से ही युद्ध का एक स्थापित क्षेत्र है। मेरा विश्वास इस विशेष क्षेत्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर आधारित है।

हमारे पास समाचार और अंतरिक्ष क्षेत्र वायु, समुद्री और थल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत दुनिया का विस्तार अनंत है। अन्य सभी सीमाओं की तरह इसकी सीमा को स्पष्ट रूप से परिभ्राष्ट करना मुश्किल है। अंतरिक्ष के हस्तय को समझके लिए मानव जाति को अभी लंबा रास्ता तय करना है। भारत उस यात्रा का हिस्सा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र के गणनायान कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ले रहे चार अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी बात की। जनरल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष को युद्ध के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मेरा मानना है कि यह पहले से ही युद्ध का एक स्थापित क्षेत्र है। मेरा विश्वास इस विशेष क्षेत्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर आधारित है।

हमारे पास समाचार और अंतरिक्ष क्षेत्र वायु, समुद्री और थल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत दुनिया का विस्तार अनंत है। अन्य सभी सीमाओं की तरह इसकी सीमा को स्पष्ट रूप से परिभ्राष्ट करना मुश्किल है। अंतरिक्ष के हस्तय को समझके लिए मानव जाति को अभी लंबा रास्ता तय करना है। भारत उस यात्रा का हिस्सा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र के गणनायान कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ले रहे चार अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी बात की। जनरल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष को युद्ध के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मेरा मानना है कि यह पहले से ही युद्ध का एक स्थापित क्षेत्र है। मेरा विश्वास इस विशेष क्षेत्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर आधारित है।

हमारे पास समाचार और अंतरिक्ष क्षेत्र वायु, समुद्री और थल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत दुनिया का विस्तार अनंत है। अन्य सभी सीमाओं की तरह इसकी सीमा को स्पष्ट रूप से परिभ्राष्ट करना मुश्किल है। अंतरिक्ष के हस्तय को समझके लिए मानव जाति को अभी लंबा रास्ता तय करना है। भारत उस यात्रा का हिस्सा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र के गणनायान कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ले रहे चार अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी बात की। जनरल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष को युद्ध के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मेरा मानना है कि यह पहले से ही युद्ध का एक स्थापित क्षेत्र है। मेरा विश्वास इस विशेष क्षेत्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर आधारित है।

हमारे पास समाचार और अंतरिक्ष क्षेत्र वायु, समुद्री और थल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत दुनिया का विस्तार अनंत है। अन्य सभी सीमाओं की तरह इसकी सीमा को स्पष्ट रूप से परिभ्राष्ट करना मुश्किल है। अंतरिक्ष के हस्तय को समझके लिए मानव जाति को अभी लंबा रास्ता तय करना है। भारत उस यात्रा का हिस्सा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र के गणनायान कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ले रहे चार अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी बात की। जनरल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष को युद्ध के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मेरा मानना है कि यह पहले से ही युद्ध का एक स्थापित क्षेत्र है। मेरा विश्वास इस विशेष क्षेत्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर आधारित है।

हमारे पास समाचार और अंतरिक्ष क्षेत्र वायु, समुद्री और थल क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत दुनिया का विस्तार अनंत है। अन्य सभी सीमाओं की तरह इसकी सीमा को स्पष्ट रूप से परिभ्राष्ट करना मुश्किल है। अंतरिक्ष के हस्तय को समझके लिए मानव जाति को अभी लंबा रास्ता तय करना है। भारत उस यात्रा का हिस्सा बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस अंतरिक्ष क्षेत्र के गणनायान कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ले रहे चार अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी बात की। जनरल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष को युद्ध के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। मेरा मानना है कि यह पहले से ही युद्ध का एक स्थापित क्षेत्र है। मेरा विश्वास इस विशेष क्षेत्र में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर आधारित है।

## खतरनाक नस्ल के कुत्तों की बिक्री पर रोक के लिए जारी होगी नई अधिसूचना

(आधुनिक समाचार नेटर्क)

नई दिल्ली। ये विश्वारेस प्राइम और लाइफ इंश्योरेस प्राइम को

